(a) the efforts made to find ways and means for payment of gratuity to the retired workers of M/s. Jessop;

(b) whether the numbers increased further and if so, the number of employees and on date who are yet to be paid post-retirement benefits; and

(c) whether with holding of payment of gratuity after retirement is a violation of Payment of Gratuity Act; if so, the action taken by Government to prevent the violation?

tHE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DR. C. SILVER A): (a) to (c) Inspite of the continuing financial problems of Jessop & Co. Ltd., it has released gratuity dues to some of the retired employees, as a result of which the number of such employees has decreased to 1,658 as on February IS, 1996. Although payment of gratuity is a statutory obligation, the company has not been able to discharge this obligation fully and regularly on account of severe financial problems. If the company turns around, such statutory obligations can be met; and the possibilities of its turn around are being examined by BIFR.

पर्यटन के विकास हेतु विदेशी धनराशि

300. **श्री राजनाथ सिंह**:

श्रीमती मालती शर्मा:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षो के दौरान पर्यटन के विकास हेतु कितनी विदेशी धनराशि प्राप्त हुई हैं;

(ख) गत वर्ष के लिए कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी और यह धनराशि किन-किन योजनाओं तथा क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई थीं;

(ग) जनवरी,1996 तक योजना-वार कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई हैं तथा कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रही हैं;और

(घ) वर्ष 1996 के दौरान समूचे उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु कितनी धनराशि स्वीकृति की गई हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (घ) भारत सरकार,पर्यटन विभाग ने बौद्व परिपथ में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष के साथ आसान शर्तो पर दो करारों पर हस्ताक्षर किए थे:-

(1) उत्तर प्रदेश और बिहार के अभिनिर्धारित बौद्व परिपथों सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 7.76 बिलियन जापानी येन उत्तर प्रदेश में सारनाथ,कुशीनगर,पिपरवाहा और श्रावस्ती तथा बिहार में बोधगया,नालन्दा,राजगीर और वैशाली अभिनिर्धारित किए गए स्थल हैं।

(2) महाराष्ट्र में अजन्ता और एलौरा के संरक्षण और पर्यटन विकास योजना के लिए 3.75 बिलियन जापानी येन।

विदेशी आर्थिक सहयोग कोष अग्रिम रूप से उपलब्ध नहीं होता हैं। कार्यान्वयन अभिकरण यथा राज्य सरकार पहले अपने संसाधनों से खर्च करती हैं और बाद में विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से प्रतिपूर्ति का दावा करती हैं।

उत्तर प्रदेश एंव बिहार परियोजना के अधीन कार्य के घटकों में,राष्ट्रीय तथा राजकीय राजमार्गो का उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण करना,स्मारकों के इर्द-गिर्द भू-दृश्यांकन करना,मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण करना तथा विद्युत व जल आपूर्ति को बढ़ाना शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के लिए 42.19 करोड़ रूपये की तथा बिहार के लिए 38.78 करोड़ रूपये की राशि की पहले ही प्रतिपूर्ति की जा चुकी हैं।

जहां तक महाराष्ट्र में परियोजना का संबंध हैं,महाराष्ट्र सरकार तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विकास तथा संरक्षण कार्यो पर क्रमशः 7.77 करोड़ रूपये तथा 0.27 करोड़ रू. खर्च किए हैं। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भी अजन्ता और एलौरा परियोजना के अंतर्गत औरंगाबाद हवाई-अड्डे के विस्तार पर 8.31 करोड़ रूपए खर्च किए हैं। विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से उपयुक्त दावों की प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा की जाती हैं।

Export order for Engines Coaches and Wagons Stock

301. SHRI MOOLCHAND MEENA:
SHRI SANJAY DALMIA: